

कपास के आयात पर सीमा शुल्क छूट 31 दिसंबर तक बढ़ी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने घरेलू वस्त्र उद्योग की कच्चे माल संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कपास के आयात पर मौजूदा सीमा शुल्क छूट को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर इस निर्णय की घोषणा की। इस संशोधन के तहत 31 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध सीमा शुल्क छूट को दो महीने के लिए बढ़ाया गया है। सरकार का उद्देश्य घरेलू वस्त्र उद्योग के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाना, उसकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना और वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करना है। इस निर्णय से वस्त्र और परिधान निर्माताओं को कच्चे माल की जरूरतें पूरी करने में अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, उत्पादन लागत पर दबाव कम होने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता मिलने की संभावना है। सरकार के अनुसार, कपास के आयात पर सीमा शुल्क छूट जारी रहने से घरेलू वस्त्र उद्योग को कच्चे माल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इससे उद्योग की परिचालन क्षमता और लचीलेपन में सुधार हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय वस्त्र उत्पादों की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होने की उम्मीद है। कपास आधारित वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिलने से उत्पादन और रोजगार के अवसरों को भी समर्थन मिल सकता है। वस्त्र मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धी, लचीले और वैश्विक स्तर पर एकीकृत वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

वस्त्र उद्योग को राहत देने के लिए केंद्र का निर्णय

कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ने और लागत दबाव कम होने की उम्मीद

नईदुनिया

31 जनवरी तक लागू रहेंगे प्रतिबंध, सीएनजी, बिजली और बीएस-6 वाहनों को नियमों के तहत छूट

दिल्ली में आज से गैर-बीएस-6 बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक



चलने वाले वाहन और बिजली से चलने वाले वाहन निर्धारित नियमों	के तहत प्रवेश कर सकेंगे। आवश्यक सेवाओं और अधिसूचना	में छूट प्राप्त वाहनों को भी प्रतिबंध से राहत मिलेगी।
--	--	---

अंतरराज्यीय बसों और मालवाहक वाहनों पर भी नियम

दूसरे राज्यों से आने वाली ऐसी डीजल बसों पर भी रोक रहेगी, जो बीएस-6 मानकों के अनुरूप नहीं हैं। दिल्ली के लिए निर्धारित न होने वाले मालवाहक वाहनों को शहर में प्रवेश करने के बजाय पूर्वी या पश्चिमी परिधीय द्रुतमार्ग का उपयोग करना होगा। लागू प्रतिबंधों के तहत ट्रेक्टर और जुगाड़ वाहनों की आवाजाही भी सीमित रहेगी। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से यात्रा शुरू करने से पहले अपने वाहन के उत्सर्जन मानक, पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने की अपील की है। वाहन चालकों को वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र साथ रखने की सलाह भी दी गई है।

प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं तो ईंधन नहीं

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 'वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं, तो ईंधन नहीं' व्यवस्था भी लागू की जाएगी। इसके तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को पेट्रोल, डीजल, संपीडित प्राकृतिक गैस और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस नहीं मिलेगी। इसके अलावा, एक नवंबर से अधिकृत पार्किंग स्थलों पर निजी वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा। बिजली से चलने वाले वाहनों को इस वृद्धि से छूट मिलेगी। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 150 नई बिजली चालित बसें जोड़ने की भी घोषणा की है। प्रशासन ने वाहन चालकों से नए नियमों का पालन करने और यात्रा से पहले अपने वाहन की पात्रता सुनिश्चित करने की अपील की है।

ख़ास-ख़बरें

नवी लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदेगी एमआईएच पेमेंट्स होल्डिंग्स प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एमआईएच पेमेंट्स होल्डिंग्स बी.वी. द्वारा नवी लिमिटेड में कुछ शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित सौदे के तहत अधिग्रहणकर्ता नवी लिमिटेड में आंशिक हिस्सेदारी खरीदेगी। एमआईएच पेमेंट्स होल्डिंग्स बी.वी. प्रोसेस एनबी की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अधिग्रहणकर्ता स्वयं अपनी निवेशित कंपनियों में निवेश करने के अतिरिक्त कोई अन्य व्यावसायिक गतिविधि नहीं करती है। उसकी निवेशित कंपनियों की भारत में व्यावसायिक गतिविधियां हैं। नवी लिमिटेड नवी समूह की मुख्य धारक कंपनी है। यह एक ही उपभोक्ता-केंद्रित मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से विभिन्न वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती है। कंपनी अपनी सहायक कंपनियों के जरिए पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है। नवी समूह की सेवाएं मोबाइल उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध हैं। कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों को एक ही मंच पर वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी के बाद प्रस्तावित अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इस सौदे में नवी लिमिटेड की कुछ शेयरधारिता का हस्तांतरण शामिल है।

आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स लिमिटेड को सोलेनर्जी पावर के अधिग्रहण की मंजूरी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स लिमिटेड द्वारा सोलेनर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड की 100 प्रतिशत जारी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रस्तावित संयोजन के तहत अधिग्रहणकर्ता विक्रेता शेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बी.वी. से लक्षित कंपनी की पूरी जारी शेयर पूंजी खरीदेगा। आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स लिमिटेड अपनी सहायक कंपनियों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के कारोबार में सक्रिय है। कंपनी और पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के साथ-साथ अपने उपयोग के लिए अभियांत्रिकी, सामग्री और निर्माण से जुड़ी गतिविधियां भी करती है। सोलेनर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड मुख्य रूप से मरीशस में पंजीकृत एक धारण कंपनी है। धारण कंपनी के कारोबार के अतिरिक्त इसका कोई अन्य व्यावसायिक संचालन नहीं है। भारत में इसकी उपस्थिति कुछ अधीनस्थ धारण संस्थाओं तथा नवीकरणीय ऊर्जा में लगी हुई हैं। प्रस्तावित अधिग्रहण के अंतर्गत आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स लिमिटेड सोलेनर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड की शत-प्रतिशत जारी शेयर पूंजी का अधिग्रहण करेगी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी देने की जानकारी 31 अक्टूबर को जारी की। आयोग की स्वीकृति अधिग्रहणकर्ता द्वारा विक्रेता से लक्षित कंपनी की पूरी जारी शेयर पूंजी खरीदने से संबंधित है।

सैफायर फूड्स का देवयानी इंटरनेशनल में विलय मंजूर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सैफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड का देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड में विलय तथा इससे जुड़े संबंधित लेन-देन को मंजूरी प्रदान कर दी है। आयोग की यह स्वीकृति प्रस्तावित संयोजन के तहत दी गई है, जिसमें सैफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड का देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड में विलय शामिल है। देवयानी इंटरनेशनल देशभर में केएफसी और पिज्जा हट के फ्रेंचाइजी केंद्रों का संचालन करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी भारत में कोस्टा कॉफी, न्यूॉर्क फ्राइज और सानूक किचन की एकमात्र फ्रेंचाइजी धारक है। देवयानी के अपने ब्रांड भी हैं, जिनका संचालन कंपनी स्वयं करती है। सैफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड भी भारत में केएफसी और पिज्जा हट के फ्रेंचाइजी केंद्रों का संचालन करती है। इस प्रकार, दोनों कंपनियां देश में इन खाद्य सेवा ब्रांडों के संचालन से जुड़ी हुई हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी प्रस्तावित विलय और उससे संबंधित लेन-देन के लिए दी गई है।

पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क खत्म, डीजल पर बढ़ाया 11.50 रुपये प्रति लीटर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और पश्चिम एशिया के तनाव के बीच सरकार का निर्णय

कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए बदला समुद्री मार्ग



युद्ध से पहले भारत अपनी जरूरत का लगभग 45 प्रतिशत कच्चा तेल होर्मुज जलडमरूमध्य के समुद्री मार्ग से आयात करता था। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही जोखिमपूर्ण हो गई। आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए भारत ने अन्य देशों से कच्चा तेल मंगाना शुरू किया है। सरकार के नए शुल्कों के तहत पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क समाप्त कर दिया गया है, जबकि डीजल और विमान ईंधन पर शुल्क बढ़ाया गया है।

ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने की बात कही गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रखे गए हैं। सरकार हर 15 दिन में बदलाव से आम उपभोक्ताओं के आधार पर निर्यात शुल्क तय करती है।

पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थीं। इस दौरान भारतीय तेल कंपनियों को विदेश में तेल बेचने पर अधिक लाभ मिलने लगा था। कंपनियों द्वारा घरेलू बाजार के बजाय विदेश में बिक्री को प्राथमिकता देने की आशंका के चलते सरकार ने मार्च में निर्यात शुल्क लागू किए थे। इसका उद्देश्य देश में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता बनाए रखना था।

मार्च में लागू किए गए थे निर्यात शुल्क

वेगा एसएस को वोडाफोन समूह में 16.2 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वेगा एसएस द्वारा वोडाफोन समूह पीएलसी की जारी शेयर पूंजी में 16.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित सौदे के तहत वेगा एसएस अधिग्रहणकर्ता और वोडाफोन समूह पीएलसी लक्षित कंपनी है। वेगा एसएस एक धारण कंपनी है और फ्रांस के कानूनों के तहत निगमित माया एसएस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। माया एसएस एक सरलीकृत संयुक्त स्टॉक कंपनी है। वेगा एसएस दूरसंचार, इंटरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार-संबंधी प्रणालियों और संचार क्षेत्र में विभिन्न उपकरणों, संजाल तथा सेवाओं के अभिकल्पन, विकास, रखरखाव, संचालन, प्रबंधन और विपणन से जुड़ी है। इसके कार्यक्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संचार संजाल की स्थापना और संचालन भी शामिल है। वेगा एसएस की भारत में स्वयं कोई व्यावसायिक उपस्थिति या गतिविधि नहीं है। भारत में

व्यावसायिक गतिविधियां उसकी संबंधित सहयोगी कंपनियों के माध्यम से संचालित होती हैं। वोडाफोन समूह पीएलसी यूरोप और अफ्रीका में कार्यरत दूरसंचार कंपनी है। यह इन क्षेत्रों में स्थिर और मोबाइल दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी का अधिकांश राजस्व मुख्य दूरसंचार संपर्क उत्पादों और सेवाओं से प्राप्त होता है। इसके कारोबार में डिजिटल सेवाएं, वस्तुओं का इंटरनेट और वित्तीय सेवाएं भी शामिल हैं। भारत में वोडाफोन समूह की उपस्थिति वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के माध्यम से है। प्रस्तावित संयोजन के तहत वेगा एसएस वोडाफोन समूह पीएलसी की जारी शेयर पूंजी में 16.2 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी।

स्पेशल ख़बर

ईंधन की बढ़ती कीमतों से वित्तीय संकट, इस साल 70 करोड़ डॉलर तक घाटे की आशंका

अलास्का एयर ग्रुप में 200 कर्मचारियों की छंटनी



विस्तार योजनाओं के बीच बढ़ा वित्तीय दबाव

अलास्का एयर ग्रुप प्रिमियम और अंतरराष्ट्रीय यात्रा क्षेत्रों में अपना कारोबार बढ़ा रहा है। मजबूत आय वृद्धि के बावजूद कच्चे तेल और विमान ईंधन की लागत में तेज उछाल से कंपनी की कमाई पर दबाव बढ़ा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि कंपनी को फिर से वित्तीय अनुशासन अपनाना होगा, जो लंबे समय से उसकी ताकत रहा है। उनके अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के संचालन संबंधी अतिरिक्त खर्च आय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़े हैं। सेवा-समाप्ति सहायता वह वित्तीय राशि है, जो कंपनी द्वारा कर्मचारी को नौकरी से हटाए जाने पर उसकी सेवा अवधि, अनुबंध और कंपनी की नीति के आधार पर दी जाती है। समायोजित कर-पूर्व घाटा कर और एकमुश्त खर्चों की गणना से पहले कंपनी के मुख्य कारोबारी प्रदर्शन को दर्शाता है।

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली:

घटते मुनाफे और बढ़ते खर्चों के बीच अलास्का एयर ग्रुप ने करीब 200 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेन मिनिक्चुी ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियां बनी रहने पर विमानन कंपनी को इस साल 70 करोड़ डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। कर्मचारियों को भेजे गए संदेश में मिनिक्चुी ने बताया कि वित्तीय संकट जारी रहने पर महामारी के दौर को छोड़कर वर्ष 2003 के बाद कंपनी को पहली बार समायोजित कर-पूर्व घाटे का सामना करना पड़ सकता है। विमानन क्षेत्र में ईंधन की बढ़ती कीमतें और वैश्विक तनाव कंपनी की वित्तीय स्थिति पर सीधा असर डाल रहे हैं।

अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस को इटैलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अधिग्रहण की मंजूरी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा इटैलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित सौदे के तहत अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस, इटैलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। इस सौदे में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। दोनों संस्थाएं लक्ष्य कंपनी की वर्तमान हिस्सेदार हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस प्रस्तावित अधिग्रहण को स्वीकृति प्रदान की है। अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस अडाणी समूह का हिस्सा है। यह भारत में पंजीकृत सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है, जिसके शेयर मुंबई स्थित बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। कंपनी मुख्य रूप से बिजली के संचारण और वितरण के क्षेत्र में कार्य करती है। इसके

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को दी स्वीकृति

बिजली और स्मार्ट मीटर क्षेत्र में विस्तार का रास्ता खुला

अतिरिक्त, बिजली क्षेत्र में उन्नत मीटरिंग आधारभूत संरचना लागू करने से संबंधित गतिविधियों में भी इसकी भागीदारी है। इटैलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड भी भारत में बिजली क्षेत्र की उन्नत मीटरिंग आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों में सक्रिय है। कंपनी बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने और उनसे संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्मार्ट गैस मीटर लगाने के कार्य में भी शामिल है। इस अधिग्रहण के माध्यम से अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस को स्मार्ट मीटरिंग क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने का अवसर मिलेगा। प्रस्तावित सौदे में लक्ष्य कंपनी की पूरी हिस्सेदारी का हस्तांतरण शामिल है।

चैटजीपीटी पर हथियारों और सुरक्षा प्रणालियों की व्यावहारिक जानकारी पर रोक

ओपनएआई ने किशोरों की सुरक्षा के लिए नियम सख्त किए

हिंसक बातचीत पर सत्र अपने-आप होगा बंद



ओपनएआई के नए सुरक्षा नियम सभी उपयोगकर्ताओं पर लागू होंगे। यदि कोई उपयोगकर्ता बातचीत के दौरान लगातार हिंसा या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी बातों पर केंद्रित रहता है, तो चैटजीपीटी उस बातचीत के सत्र को अपने-आप बंद कर देगा। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई उपयोगकर्ता बार-बार हिंसक विषयों पर बातचीत करने या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास करता है, तो उसका खाता अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है।

जानकारा दा है। इन नियमों के तहत हथियारों और सुरक्षा प्रणालियों से संबंधित ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, जिसका व्यावहारिक उपयोग नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता हो।

किशोरों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान

नए उपायों में किशोरों को हथियारों और सुरक्षा प्रणालियों से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी से दूर रखने पर विशेष जोर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि संभावित दिखने वाले प्रश्नों के पीछे भी सभ्यताई जोखिम हो सकते हैं, इसलिए ऐसे विषयों पर जावब देने के नियम अधिक सख्त किए जा रहे हैं। इन सुरक्षा व्यवस्थाओं के तहत हिंसक बातचीत की स्थिति में अभिभावकों को सूचना दिए जाने की व्यवस्था भी शामिल होगी।

आईफोन एयर 2 में मिल सकता है दूसरा कैमरा बैटरी भी होगी बड़ी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: एप्पल अपने पतले स्मार्टफोन आईफोन एयर के अगले संस्करण आईफोन एयर 2 पर काम कर रही है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, नए फोन में पिछले मॉडल की तुलना में कई सुधार देखने को मिल सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख बदलाव पीछे की ओर दो कैमरे और बड़ी बैटरी का होना बताया जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस फोन के बारे में आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। आईफोन एयर अपनी बेहद पतली बनावट के कारण दुनियाभर में लोकप्रिय हुआ है। इसकी मोटाई लगभग 5.6 मिलीमीटर बताई गई है। पिछले संस्करण में पीछे की ओर एक ही कैमरा था। नई जानकारी के अनुसार, आईफोन एयर 2 में दो कैमरे दिए जा सकते हैं। इनमें मुख्य कैमरे के साथ अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल होने की संभावना है। दोनों कैमरों के 48 मेगापिक्सल के होने की चर्चा है। रिपोर्टों के मुताबिक, नए फोन में पहले की तुलना में बड़ी बैटरी दी जा सकती है। मौजूदा आईफोन एयर में लगभग 3,149 मिलीएम्पियर-घंटे की बैटरी है, जबकि अगले संस्करण में इसकी क्षमता करीब 3,500 मिलीएम्पियर-घंटे तक हो सकती है। इससे फोन की बैटरी क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है।

कुल कर्मचारियों के एक प्रतिशत से कम प्रभावित

कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार, छंटनी से उसके कुल 32,500 कर्मचारियों में एक प्रतिशत से भी कम प्रभावित होंगे। इनमें वाशिंगटन राज्य के 125 और हवाई के 48 पद शामिल हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले या गैर-प्रबंधकीय कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। प्रभावित कर्मचारियों के लिए 13 नवंबर अंतिम कार्यदिवस होगा। हालांकि, कंपनी उन्हें 31 दिसंबर तक नियमित वेतन देती रहेगी। इसके अतिरिक्त प्रभावित कर्मचारियों को सेवा-समाप्ति सहायता और अन्य वित्तीय तथा रोजगार संबंधी सहयोग भी दिया जाएगा।